स्मार्ट मीटर वालों को 20 फीसदी सस्ती मिलेगी बिजली

ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 2 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बिजली सबकी जरूरत है. सबको जरूरत के अनुसार बिजली उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. बिजली सस्ती दरों पर मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर मॉडल सबसे अच्छा है, इसलिए विद्युत उपभोक्ताओं के हित में सबके घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएं. इससे उपभोक्ताओं को 20 प्रतिशत सस्ती दर पर बिजली मिलेगी. वहीं अब प्रदेश के 6 शहरों में एक-एक विद्युत पुलिस थाने भी खोले जाएंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभों का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें उपभोक्ता को खुद की खपत का आंकलन कर ऊर्जा का अपनी सुविधानुसार उपयोग कर अपने बिजली बिल की राशि को कम से कम करने की सुविधा भी मिलती है. उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को स्मार्ट मीटर लगाने की गति को और तेज करने के निर्देश दिये. बताया गया कि प्रदेश में 1.34 करोड़ घरेलू स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं. लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 21 लाख से भी अधिक घरेलू स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं.

सालभर मेंटेनेंस करें: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मई-जून में विभिन्न स्थानों पर हुए विद्युत अवरोधों पर चर्चा करते हुए कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए साल भर मेंटेनेंस गतिविधियां चलाई जाएं, ताकि आंधी, पानी या अन्य किसी घटना के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित न हो. उन्होंने कहा कि

मेंटेनेंस गतिविधियों में नई एप्रोच के साथ नए उपाय किए जाएं. नये उपकरण क्रय किये जाएं. जहां घने पेड़ हैं, उनके नीचे से गुजरने वाले बिजली के तारों में कोटिंग कराएं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि घरेलू हो या औद्योगिक सभी जगह विद्युत का उपयोग बढ़ रहा है. इसलिए घरेलू और औद्योगिक संस्थानों को सोलर पॉवर के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए. इससे उपभोक्ता अपनी बिजली स्वयं पैदा कर अतिरिक्त बिजली बेच भी सकेगा. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में विद्युत उपयोग को भी सोलर पॉवर से चलित पम्पों पर शिफ्ट किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जरूरत वाले जिलों में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग यूनिट की स्थापना के लिए विभागीय नीति तैयार कर लें. उन्होंने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा विभाग मिलकर प्रयास करें.

> **बिजली कंपनियों को दो वर्ष में लाएं लाभ की स्थिति में**
>
> मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अगले दो साल में तीनों विद्युत वितरण कंपनियां लाभ की ?स्थिति में आ जाएं इसके लिए विद्युत कंपनियां अपनी आय के साधन बढ़ाने के प्रयास करें. नई तकनीक इस्तेमाल करें, नवाचार करें, ताकि कंपनी के साथ-साथ उपभोक्ताओं को फायदा मिले.

प्रदेश के छह महानगरों में खोले जाएंगे विद्युत पुलिस थाने

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में ऊर्जा पुलिस संरचना स्थापित की जाएगी. पहले चरण में प्रदेश के छह महानगरों में एक-एक यानी कुल 6 विशेष विद्युत पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे. आगामी वर्षों में सभी जिला मुख्यालयों में यह पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे. ये पुलिस थाने चेकिंग अभियान के दौरान चेकिंग दस्तों को सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे. औचक निरीक्षण करेंगे और केस डायरी भी तैयार करेंगे. विद्युत अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे और अदालती कार्यवाही का अवलोकन भी करेंगे ताकि डिस्कॉम की सम्पत्ति की सुरक्षा और बकाया राशि की वसूली के लिए बकाया वसूली अधिनियम के तहत कार्यवाही करेंगे. बैठक में बताया गया कि शासकीय कार्यालयों में 15 अगस्त से प्री-पेड मीटर लगाने का कार्य शुरू होगा. इससे शासकीय कार्यालयों में लंबित बिजली बिलों की समस्या नहीं होगी.

> **वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू होगी**
>
> ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बिजली बिल की बकाया राशि के समाधान के लिए विभाग द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम प्रारंभ की जा रही है. घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को उनकी मूल बिजली बिल राशि में अधिभार की छूट देकर बकाया राशि जमा करने की सुविधा दी गई है. यह स्कीम छह माह की अवधि के लिए लागू की जाएगी. इस अवधि के बाद भी बिजली बिल भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री लुधियाना में होने वाले इंटरेक्टिव सेशन में लेंगे हिस्सा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 2 जुलाई. मप्र में निवेश के नए द्वार खोलने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में चल रही औद्योगिक संवाद श्रृंखला में प्रमुख इंटरएक्टिव सेशन लुधियाना में 7 जुलाई को होने जा रहा है. बैंगलुरु और सूरत में निवेशकों से मिले सकारात्मक प्रतिसाद के बाद अब लुधियाना में तीसरा इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपोर्चूनिटीज इन मप्र आयोजित होगा.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव लुधियाना के प्रमुख उद्योगपतियों, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के निवेशकों के साथ सीधे संवाद करेंगे. यह आयोजन केवल विचारों के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें संभावित निवेश प्रस्तावों पर ठोस चर्चा भी की जाएगी. मप्र की नई औद्योगिक नीति, सेक्टर-फोकस्ड रणनीतियां और ग्राउंड-रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इस संवाद का केंद्रीय आकर्षण होंगे. लुधियाना की पहचान भारत के विनिर्माण हब के रूप में रही है, विशेष रूप से वस्त्र और मशीनरी निर्माण में लुधियाना की विशेष पहचान है. ऐसे में इस क्षेत्र के उद्यमियों का ध्यान मप्र में निवेश की संभावनाओं की ओर आकृष्ट करने के लिए यह सेशन महत्वपूर्ण साबित होगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव राज्य की विशेष औद्योगिक परियोजनाओं — जैसे एमपी टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्रा पार्क, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर विस्तार से जानकारी देंगे.

सतना की अर्चना राज्य शासन से होंगी सम्मानित

सतना, 2 जुलाई. मप्र शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार सत्र 2020-21 के लिए शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक अर्चना कुशवाहा का चयन किया गया है.

अर्चना जिले की नागौद तहसील अंतर्गत अमकुई ग्राम की निवासी हैं, अर्चना की माने तो यह पुरस्कार उन्हें भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाए जाने

वाले जागरुकता कार्यक्रमों में शिक्षा के साथ-साथ स्वैच्छिक सामाजिक सरोकार के कार्यों में विगत वर्षों में वृक्षारोपण, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, नेत्र शिविर, मतदाता जागरूकता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, कोविड 19 महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद करने एवं जरूरत की चीज को मुहैया कराने एवं अन्य जागरुकता कार्यक्रमों में सहभागिता कर उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है. इसके पूर्व अर्चना को 24 सितंबर 2022 को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार सत्र 2020-21, सतना गौरव सम्मान 2023, विंध्य गौरव अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया जा चुका है.

शिक्षिका के तबादले पर रोक

जबलपुर, 2 जुलाई. मप्र हाईकोर्ट ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नरई नाला जबलपुर में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक नेहा जैन के स्थानांतरण पर रोक लगा दी. जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने अगली सुनवाई तक राज्य शासन को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है.

जबलपुर निवासी नेहा जैन की ओर से अधिवक्ता वंदना त्रिपाठी ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता का चयन विशेष रूप से एकलव्य विद्यालय में पदस्थापना के लिए हुआ था. शासन द्वारा उन्हें एक गैर-एकलव्य संस्था शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मंडला में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो नीति के विरुद्ध है. उन्होंने बताया कि 17 फरवरी 2025 के विभागीय परिपत्र के तहत याचिकाकर्ता से स्थान चयन हेतु पांच विकल्प लिए गए थे. जिनमें मंडला के दो विद्यालय भी शामिल थे, परंतु उन्हें किसी भी विकल्प वाले विद्यालय में स्थानांतरित नहीं किया गया.

यात्री बस आगे चल रहे ट्रक में घुसी

ड्राइवर-कंडक्टर ने की ट्रक चालक से मारपीट, वीडियो वायरल

सलामतपुर, 02 जुलाई. भोपाल-विदिशा स्टेट हाईवे-18 पर बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया. बालमपुर पेट्रोल पंप के सामने शक्ति कंपनी की एक तेज़ रफ्तार यात्री बस आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी.

टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि सौभाग्यवश यात्रियों को केवल मामूली चोटें आईं और एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. हादसे के तुरंत बाद बस ड्राइवर और कंडक्टर आपा खो बैठे और ट्रक चालक के साथ जमकर मारपीट कर दी. मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ड्राइवर-कंडक्टर की गुंडागर्दी साफ नज़र आ रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यात्री बस विदिशा से भोपाल की ओर जा रही थी.

> **इनका कहना है.**
>
> शीघ्र ही बसों की तेज रफ्तार पर अंकुश लगाया जाएगा. ऐसे तेज़ रफ्तार चार्टर्ड बसों पर चालानी कार्रवाई कर समझाईश दी जाएगी.
>
> **दिनेश सिंह रघुवंशी,** थाना प्रभारी सलामतपुर

नवविवाहिता ने की आत्महत्या

बेगमगंज. एक नवविवाहिता द्वारा बुधवार को अपनी ससुराल में घरेलू हिंसा से प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि बुधवार दोपहर एक नवविवाहिता उरूसा बी पति मुशीर खां 23 वर्ष निवासी कटरा मोहल्ला बेगमगंज के द्वारा अपनी ससुराल में ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली. मृतका का एक वर्षीय पुत्र है. ससुराल पक्ष के लोग उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे . जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया . घटना की सूचना डॉक्टर द्वारा पुलिस को दी गई

एमपी में पहली बार लगाया आर्टिफिशियल जबड़ा

भोपाल, 2 जुलाई. एम्स भोपाल में मध्य भारत की पहली कृत्रिम जबड़ा प्रत्यारोपण सर्जरी (Artificial Jaw Replacement Surgery) एक कस्टम-निर्मित टाइटेनियम इम्प्लांट की सहायता से सफलतापूर्वक की गई. यह सर्जरी पूरी तरह से कम्प्यूटर सहायता प्राप्त तकनीक से योजनाबद्ध की गई.

यह सर्जरी एक 62 वर्षीय महिला पर की गई, जो लंबे समय से गंभीर जबड़े के दर्द, चेहरे की विकृति, खाने-पीने तथा बोलने में असमर्थता जैसी समस्याओं से पीड़ित थीं. इससे पूर्व वे एक निजी अस्पताल में दो बार पारंपरिक टाइटेनियम प्लेट्स द्वारा जबड़े का

पुनर्निर्माण करवा चुकी थीं, जो असफल रही और दोनों बार प्लेट्स टूट गईं.

मरीज ने कई अस्पतालों में परामर्श लिया, जहाँ जाँच के उपरांत यह पाया गया कि उनकी स्थिति पारंपरिक उपचार विधियों से ठीक नहीं हो सकती. विभिन्न अस्पतालों में जाँच एवं परामर्श करने के बाद भी मरीज एवं उनके परिजनों को कोई राहत नहीं मिली. तब उन्होंने एम्स भोपाल के ट्रॉमा एवं आपातकालीन विभाग में संपर्क किया.

> इसके पश्चात, डॉ. बी. एल. सोनी (मैक्सिलोफेशियल सर्जन) के नेतृत्व में चिकित्सकीय टीम ने रोगी की स्थिति का गहन मूल्यांकन कर एक नवीन और अनुकूलित समाधान प्रस्तुत किया. इस प्रक्रिया में वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग और सटीक मिलिंग तकनीक का उपयोग किया गया. डॉ. सोनी ने रोगी के मेडिकल इमेजिंग और इन-हाउस सॉफ्टवेयर की सहायता से इस इम्प्लांट को डिजाइन किया.

झूठा मुकदमा दर्ज करने के विरोध में प्रदर्शन

निष्पक्ष जांच को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

बैरसिया, 2 जुलाई. बुधवार को सैकड़ों लोगों द्वारा कृषि मंडी से रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय गेट पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की सात दिन में जांच कर कार्रवाई की मांग की है.

मामले में विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे अखिल भारतीय राष्ट्रीय यादव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव दामोदर यादव ने मामले पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीते दिनों किसान नेता राजू यादव और उनके दो अन्य साथियों पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है. गांव की रंजिश के चलते हो या राजनैतिक षड्यंत्र

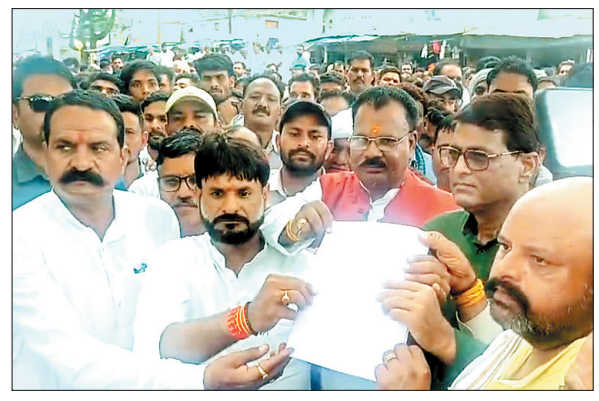

के चलते हो लेकिन झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया है. उसी के विरोध में आज सारे समाज और सारे राजनीतिक दलों के लोग यहां आए हैं. हम सभी ने एसडीएम और पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए जल्दी से जल्दी उन सबको दोस्त मुक्त करके बाहर निकल जाए और झूठी एफआईआर को खत्म किया जाए. यादव का आरोप है कि जो घटना घटित हुई है वह कहीं-न-कहीं रेवेन्यू विभाग की लापरवाही से हुई है.

आरोप है कि मामले में तहसीलदार ने दो तरह के निर्णय लिए थे जिससे विवाद की स्थिति बनी हमने एसडीएम से कहा है कि मामले वें स्वयं जांच करें और जो अधिकारी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें सात दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तों बड़ा आंदोलन भोपाल में करेंगे.

सीएम डॉ. यादव सहित 44 भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य निर्वाचित

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लिये चुनाव प्रभारी बनाये

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 2 जुलाई. भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित 44 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गये हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिये नामांकन भरने के साथ ही राष्ट्रीय परिषद सदस्य के लिये भी नामांकन जमा किये गये थे.

बुधवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लिये चुनाव प्रभारी बनाये गये केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा की. इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अलावा शिवराजसिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, वीरेंद्र खटीक, जगदीश देवड़ा, राजेन्द्र शुक्ल, प्रहलाद पटेल , राकेश सिंह, सावित्री ठाकुर, डीडी उइके, फग्गन सिंह कुलस्ते, लाल सिंह आर्य, सत्य नारायण जटिया, ओमप्रकाश धुर्वे, जयभान सिंह पवैया, हिमाद्रि सिंह, भारती पारधी, इंदर सिंह परमार, सुधीर गुप्ता, गणेश सिंह, नीना वर्मा, कांतदेव सिंह, गोपाल भार्गव, आलोक संजर, उमाशंकर गुप्ता, कमल पटेल, गौरीशंकर बिसेन, अर्चना चिटनिस, कविता पाटीदार के नाम भी शामिल हैं.

अब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना हुआ आसान

बीएमओ ने की योजना की समीक्षा

बैरसिया, 2 जुलाई. अब आयुष्मान भारत निरामय मध्यप्रदेश हेल्पलाइन (1800 233 2085) के माध्यम से सभी शासकीय एवं आयुष्मान पंजीकृत निजी अस्पतालों में डॉक्टर से परामर्श हेतु अपॉइंटमेंट लेना बेहद आसान हो गया है.

बीएमओ डॉ.पुष्पा गुरु ने बुधवार को अस्पताल में इसकी समीक्षा उपरांत बताया मरीज इस टोल-फ्री हेल्पलाइन पर कॉल करके घर बैठे ही ओपीडी का नंबर बुक कर सकते हैं. इससे समय की

बचत होती है और अस्पताल में बेहतर एवं त्वरित उपचार संभव हो पाता है. यह सुविधा सभी आयु वर्ग और सभी सामाजिक पृष्ठभूमि के मरीजों के लिए पूरी तरह निःशुल्क है. केवल एक कॉल के माध्यम से न सिर्फ अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है, बल्कि आभा आईडी (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट) और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (ईएचआर) भी बनवाए जा सकते हैं. ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) डॉ. पुष्पा गुरु ने बताया कि यह सेवा मरीजों को अस्पताल में लंबी कतारों से बचाती है और ओपीडी में प्राथमिकता भी दिलाती है. उन्होंने अपील की कि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ लें और दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी दें.

> बीएमओ ने बताया कि बैरसिया के ग्राम बिरहा श्यामखेड़ी में यह सेवा विशेष रूप से लोकप्रिय हो चुकी है. वहां की आशा कार्यकर्ता प्रेमलता कुशवाह ने घर-घर जाकर इस हेल्पलाइन की जानकारी दी, जिससे अब यहा के अधिकांश लोग अपॉइंटमेंट लेकर ही अस्पताल जाते हैं. अब तक बैरसिया ब्लॉक में कुल 4480 अपॉइंटमेंट हेल्पलाइन के माध्यम से लिए जा चुके हैं. मरीजों द्वारा दिए गए फीडबैक के अनुसार इस सेवा को औसतन 9.1 की रेटिंग प्राप्त हुई है – जो लोगों की संतुष्टि को दर्शाता है.

वनतारा की तरह प्रदेश में बनेगा सेंटर

वन्य जीव संरक्षण को लेकर नवाचार

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 2 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य में जियो और जीने दो की भावना को केंद्र में रखकर सह-अस्तित्व आधारित ईको-सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे न केवल जैव विविधता का संरक्षण हो रहा है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है और वनवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं.

प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में कई नवाचार किए जा रहे हैं इनमें वन्यजीव अभयारण्यों के संरक्षण और प्रबंधन में उच्च तकनीक का अनुप्रयोग, गुजरात के 'वनतारा' से प्रेरित रेस्क्यू सेंटर, दुर्लभ जीवों जैसे चीते, घड़ियाल एवं कछुओं के एक अभयारण्य से दूसरे में पुनर्स्थापन और संरक्षित क्षेत्रों की फेंसिंग शामिल हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन विभाग के अधिकारियों को गुजरात के 'वनतारा' वन्यजीव पुनर्वास केंद्र का अध्ययन कर प्रदेश में भी ऐसा ही रेस्क्यू और एनिमल वेलफेयर प्रोजेक्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि यह पहल वन्यजीवों के संरक्षण और पुनर्वास में एक नई मिसाल पेश करेगी.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के घने वनों और वन्यजीव पर्यटन को राजस्व वृद्धि का एक प्रमुख माध्यम बताया. उन्होंने वन अधिकारी-कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधाओं और उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रोत्साहन की घोषणा की. उन्होंने यह भी बताया कि वन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों से प्रदेश में वन क्षेत्र और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

प्रदेश में वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जारी है. जैव-विविधता को बढ़ावा देने के लिए कई स्थलों को जैव-विविधता विरासत घोषित किया गया है. वन-अग्नि की घटनाओं पर विभाग की प्रतिक्रिया अब पहले से अधिक त्वरित हुई है, जो प्रभावी वन प्रबंधन को दर्शाता है.

उपलब्धि | लोकपथ मोबाइल ऐप को एक वर्ष पूरा

एक साल के सफर में 85 फीसदी शिकायतों का समाधान

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 2 जुलाई. मप्र में लोक निर्माण द्वारा शुरू किये गये लोकपथ मोबाइल ऐप को एक वर्ष पूरा हो गया है. आम लोगों द्वारा खराब सड़कों की शिकायत करने पर इस प्लेटफार्म के माध्यम से सड़कों के तुरंत रियेपर का प्रावधान किया गया है.

इस ऐप के एक साल के सफर में 7800 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 95 प्रतिशत से अधिक का त्वरित समाधान कर दिया गया है. लगभग 1.5 लाख नागरिकों द्वारा ऐप को डाउनलोड किया जाना यह दर्शाता है कि जनता में इसकी उपयोगिता और विश्वसनीयता को लेकर गहरी स्वीकार्यता बनी है.

बुधवार को लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में इस अवसर पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ऐप के अब तक की सफलता, नागरिकों की भागीदारी और आगामी लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की गई. ऐप की सफलता पर मंत्री सिंह ने विभागीय अधिकारियों को बधाई देते हुए लोकपथ ऐप को जनभागीदारी आधारित डिजिटल गवर्नेंस का प्रभावी उदाहरण बताया. उन्होंने

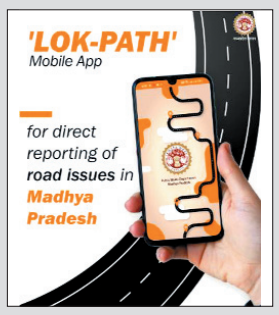

कहा कि आने वाले वर्ष में ऐप के 5 लाख डाउनलोड सुनिश्चित करने का लक्ष्य है, जिसके लिए व्यापक जनजागरण और प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा. लोकपथ ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली जब कौन बनेगा करोड़पति जैसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने इससे संबंधित प्रश्न प्रस्तुत किया. इससे यह स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश का यह नवाचार अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणास्रोत बन चुका है. मंत्री ने बैठक में प्रमुख अभियंताओं को साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य रूप से करने तथा लंबित शिकायतों को लेकर लापरवाह अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा.

> **नगर निगम, एनएचएआई और राजमार्गों को भी लोकपथ से जोड़ने का सुझाव**
>
> बैठक में यह सुझाव भी आया कि नगर निगम की सड़कों को भी लोकपथ ऐप से जोड़ा जाए, जिससे नगरीय क्षेत्रों में भी सड़क समस्याओं का समाधान इसी प्लेटफॉर्म से हो सके. एनएचएआई के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों को लोकपथ से जोड़ने की प्रक्रिया पर भी विचार किया जा रहा है, जो आने वाले समय में राज्य के समग्र सड़क नेटवर्क प्रबंधन में क्रांतिकारी सुधार ला सकती है.

तीन अधिकारियों पर अवमानना की कार्यवाही के आदेश

जबलपुर. हाईकोर्ट ने अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज बीपी पाण्डेय, सीईओ जनपद पंचायत मऊगंज राम कुशल मिश्रा और बीआरसीसी शिव कुमार रजक के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिये. जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री को तीनों अधिकारियों के खिलाफ पृथक से अवमानना याचिका दाखिल करने के निर्देश दिये है. पूर्व आदेश के पालन में बुधवार को तीनों अधिकारी हाजिर हुए और कोर्ट से बिना शर्त माफी भी मांगी. दरअसल हाईकोर्ट ने पूर्व में दायर एक याचिका पर निर्देश दिए थे नए सिरे से तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच करें.

> सीएम ने बताया कि प्रदेश में आधुनिक चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर्स विकसित किये जा रहे हैं. उज्जैन और जबलपुर में उन्नत सुविधाओं से युक्त नये चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर शीघ्र ही स्थापित किए जा रहे हैं. ओंकारेश्वर, ताप्ती और बालाघाट के सोनेवानी क्षेत्र में नए कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जा रहे हैं, जो वन्यजीव आवासों की रक्षा करेंगे. प्रदेश के बुंदेलखंड वन क्षेत्रों में फैले हुए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीता पुनर्स्थापना की तैयारियां चल रही हैं, जिससे जैव विविधता में वृद्धि होगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्पष्ट किया कि टाइगर रिजर्व की घोषणा से जनजातीय समुदायों और वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं होने दिया जायेगा और उनका पूर्ण सम्मान किया जाएगा. सह-अस्तित्व के लिए सह-प्रबंधन की नीति अपनाई जाएगी और जहाँ आवश्यक होगा वहां पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जाएगी.